AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International

ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue:3
December 2023
Impact Factor: 11.9
Subject: Political Sience

बिहार के सुपौल जिले में ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और समाज पर इसका प्रभाव का एक अध्ययन

नीरज कुमार ठाकुर, डॉ. विनोद कुमार सैनी

[1]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान, भारत

[2]शोध निर्देशक, राजनीति विज्ञान, भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान, भारत

DECLARATION: I AS AN AUTHOR OF THIS PAPER /ARTICLE, HERE BY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BY ME FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL IS COMPLETELY MY OWN GENUINE PAPER.IFANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT/PATENT/ OTHER REAL AUTHOR ARISES, THE PUBLISHER WILL NOT BELEGALLY RESPONSIBLE. IF ANY OF SUCH MATTERS OCCUR PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL WEBSITE .FOR THE REASON OF CONTENT AMENDMENT/OR ANY TECHNICAL ISSUE WITH NO VISIBILITY ON WEBSITE/UPDATES, I HAVE RESUBMITTED THIS PAPER FOR THE PUBLICATION. FOR ANY PUBLICATION MATTERS OR ANY INFORMATION INTENTIONALLY HIDDEN BY ME OR OTHERWISE, ISHALL BELEGALLY RESPONSIBLE (COMPLETE DECLARATION OF THE AUTHOR AT THE LAST PAGE OF THIS PAPER/ARTICLE

सारांश

बिहार में, दुनिया के कई अन्य लोकतंत्रों की तरह, निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व एक प्रमुख चिंता का विषय है। अन्य जगहों पर, लगभग आधी आबादी का गठन करने वाली महिलाएं सरकार के विभिन्न स्तरों के भीतर केवल नियुक्ति और वैकल्पिक राजनीतिक कार्यालयों का एक अंश हैं। बिहार में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व कुछ हद तक विरोधाभास है। एक ओर, महिलाओं की भागीदारी के रूप में, एक मतदाता लैंगिक समानता तक पहुंच गया है, जबकि दूसरी ओर राजनीतिक नेतृत्व में वास्तविक भूमिका निभाने वाली महिलाओं का अनुपात बहुत कम है। उच्चतम निर्णय लेने वाले निकायों में कोई महिला नहीं है जो राजनीतिक निर्णय लेते हैं और राज्य को निर्देशित करते हैं। वास्तव में, बहुत कम महिलाएं हैं जो वास्तव में राजनीतिक शक्ति की तलाश करती हैं और जीतती हैं जो पुरुषों से उनके राजनीतिक व्यवहार को अलग करती हैं। यह महत्वपूर्ण अंतर वास्तविकता है जिससे यह जांच शुरू होती है। यह एक कड़वा तथ्य है कि इन मतभेदों की इतनी कम जांच की गई है क्योंकि राजनीति प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी के बारे में सवाल शायद ही कभी उठाए गए हों। राजनीति में महिलाओं के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया है। लेकिन आज जब राजनीति की सफलता और लोकतंत्र की गुणवत्ता को इसकी समावेशिता से परिभाषित किया जाता है, तो राजनीति में महिलाओं की बढ़ती संख्या महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए, वर्तमान अध्ययन राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के सवाल के संभावित जवाबों की एक श्रृंखला प्रदान करने का एक प्रयास करेगा। यह बिहार में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व में निरंतरता और परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करेगा। इसमें बिहार में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और सरकार

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue:3
December 2023
Impact Factor: 11.9
Subject: Political Sience

के स्थानीय और राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व की चर्चा की जाएँगी। वर्तमान अध्ययन महत्वपूर्ण प्रश्नों को संबोधित करने का प्रयास किया गया है जैसे कि महिलाओं के पास सत्ता की राजनीति में भाग लेने की क्षमता है।

मुख्य शब्दः श्रृंखला, राजनीति, चर्चा, भागीदारी और प्रतिनिधित्व

परिचय

ग्रामीण महिलाएं समाज के सतत विकास के लिए आवश्यक परिवर्तनकारी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिवर्तनों की उपलब्धि में उत्प्रेरक की भूमिका निभाती हैं। निर्णय लेने और राजनीतिक भागीदारी के सभी स्तरों पर पुरुषों के साथ समान शर्तों पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी समानता, ग्रामीण विकास, शांति और लोकतंत्र की उपलब्धि और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनके दृष्टिकोण और अनुभवों को शामिल करने के लिए आवश्यक है।

उनके जीवन को प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों पर कानूनों, रणनीतियों, नीतियों और कार्यक्रमों को आकार देने में ग्रामीण महिलाओं का नेतृत्व और भागीदारी। यह स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से संभव है। राजनीतिक सशक्तिकरण ग्रामीण महिलाओं को भूमि, नेतृत्व, अवसरों और कानूनों, विनियमों, नीतियों और कार्यक्रमों को आकार देने में भाग लेने के विकल्पों पर अपने अधिकारों का दावा करने में मदद करता है।

ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण न केवल देश के लोकतंत्र को मजबूत करने, हाशिए पर जाने, तुच्छीकरण और उत्पीड़न के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए आवश्यक है, बल्कि उनके सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण महिलाओं को अपने कानूनी और राजनीतिक अधिकारों के बारे में जानकारी या जागरूकता नहीं है, इसलिए वे अपने समुदायों के चुनावों और राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लेती हैं। ग्रामीण महिलाओं का संस्थानों, शासन और नेतृत्व में प्रतिनिधित्व कम है और उनमें निर्णय लेने की शक्ति भी कम है।

तिहत्तरवें संवैधानिक संशोधन (1993) के अधिनियमन ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन इकाई के रूप में मजबूत सक्षम और ऊर्जावान पंचायतों के उद्देश्य से त्रि–स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना को अनिवार्य कर दिया, जो भारत में एक क्रांतिकारी कदम है। ग्रामीण लोगों को ग्राम पंचायत, तहसील या ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत के माध्यम से शक्ति देने का आदेश दिया गया था, जिसमें नियमित रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे। ये प्रतिनिधि स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार विकास की योजना बनाने और सेवाएं प्रदान करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

जिले के ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं किसान, मजदूरी कमाने वाले और उद्यमी के रूप में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे अपने परिवार के सदस्यों की भलाई की जिम्मेदारी भी लेते हैं, जिसमें भोजन प्रावधान, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल, पशुधन की देखभाल शामिल है, और कृषि बल के काम में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वे अत्यधिक गरीबी, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और कम आर्थिक उत्पादकता से पीड़ित हैं। उनमें से

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue:3
December 2023
Impact Factor: 11.9
Subject: Political Sience

अधिकांश असंगठित क्षेत्रों, कृषि या अन्य संबद्ध गतिविधियों की कम आय वाली नौकरियों में शामिल हैं।

अध्ययन महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में वृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के बीच सकारात्मक सहसंबंध दिखाता है। यह संभव है कि चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी, नेतृत्व की गुणवत्ता और निर्णय लेने की शक्ति विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भागीदारी के माध्यम से जिले के विकास को गति देने में योगदान देगी।

उद्देश्य

(i) विभिन्न स्तरों पर पंचायत चुनावों में ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी निर्धारित करना।

(ii) जिले के सामाजिक–आर्थिक विकास में योगदान बढ़ाने के लिए ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, भागीदारी और सशक्तिकरण के लिए संभावित समाधान सुझाना।

अनुसंधान क्रियाविधि

प्रस्तावित अध्ययन मुख्यतः वर्णनात्मक प्रकृति का है। यह शोध पत्र बिहार राज्य निर्वाचन आयोग, सुपौल की पंचायत चुनाव रिपोर्टों से एकत्रित द्वितीयक आंकड़ों और सूचनाओं पर आधारित है। यह पेपर मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण और समाज पर इसके प्रभाव पर केंद्रित है।

मध्य प्रदेश चुनाव आयोग की पांचवें पंचायत चुनाव (2014–15) की रिपोर्ट के अनुसार, जिला सुपौल से 4301 पंच (वार्ड सदस्य), 256 सुरपंच (प्रधान), 100 जनपद पंचायत सदस्य और 13 जिला पंचायत सदस्य चुने गए हैं। महिला वर्ग से 2247 पंच (वार्ड सदस्य), 130 सुरपंच (प्रधान), 52 जनपद पंचायत सदस्य और 7 जिला पंचायत सदस्य चुने गए हैं।

तालिका 1.1: पांचवें पंचायत चुनाव में ग्रामीण महिलाओं का प्रतिनिधित्व (2014–15)

क्र. सं.	प्रतिनिधि पद	महिला प्रतिनिधि		
		कुल सीटें	महिला प्रतिनिधि	प्रतिशत
1.	पंच (वार्ड सदस्य)	4301	2247	52.24
2.	सुरपंच (प्रधान)	256	130	50.78
3.	सदस्य जनपद पंचायत	100	52	52.00
4.	सदस्य जिला पंचायत	13	07	53.84
	कुल	**4670**	**2436**	**52.16**

ग्रामीण महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के माध्यम से वह महिलाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में सोच और विश्लेषण कर सकती हैं और उन सामाजिक मानदंडों और बाधाओं की पहचान कर सकती हैं, जो उनकी प्रगति में बड़ी बाधाएं हैं, जिससे वे महिला अनुकूल कानूनों,

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue:3
December 2023
Impact Factor: 11.9
Subject: Political Sience

विनियमों, नीतियों के निर्माण में भाग लेने और उचित बदलाव करने में सक्षम हो सकें। कार्यक्रम और निर्णय लेने की प्रक्रिया। वे सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रभावी उपाय पेश करते हैं और जीडीपी बढ़ाने में योगदान देते हैं।
सुरपंच सदस्य, जनपद पंचायत और सदस्य जिला पंचायत के रूप में महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व में सरकारी अधिकारियों के समन्वय के साथ विभिन्न समितियों यानी योजना समिति, विकास और वित्त समिति के माध्यम से ग्राम विकास में सक्रिय भूमिका निभाई जाती है। वे गाँव से जुड़ी सड़कों, आंतरिक सड़कों, पेयजल सुविधाओं, शौचालयों, स्कूलों, औषधालयों, खेल के मैदानों और आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण में भी योगदान देंगे। उन्होंने जल संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण संबंधी कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित किया।

जाँच – परिणाम

(i) महिला प्रतिनिधि ज्यादातर ग्राम पंचायत स्तर पर अपने पुरुष परिवार के सदस्य के मुखपत्र के रूप में कार्य करती हैं।
(ii) शिक्षा की कमी, राजनीतिक ज्ञान की कमी, लिंग और सामाजिक मानदंड या सामाजिक बाधाएं, घरेलू और अन्य क्षेत्रों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में कम भागीदारी, ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा हैं।
(iii) ग्रामीण महिलाओं की विशाल क्षमता सामाजिक–आर्थिक विकास में योगदान करती है और जीडीपी बढ़ाती है। यदि समानता की बाधाओं को दूर किया जाता है।
ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पंचायत के लिए आरक्षण नीति के कारण कुछ महिलाएं पंचायत में चुनी गईं। लेकिन उन्होंने केवल अपने पुरुष परिवार के सदस्यों के मुखपत्र के रूप में काम किया, इसलिए हम कई महिला प्रतिनिधियों की राजनीतिक भागीदारी को प्रॉक्सी उम्मीदवार के रूप में देखते हैं। वे समुदाय को उनकी पसंद, क्षमता और जमीनी हकीकत के अनुसार सेवाएं नहीं देते हैं। उन्हें कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है जैसे शिक्षा की कमी, कम कौशल, कम उत्पादकता, खराब कामकाजी स्थितियां, सीमित सामाजिक सुरक्षा, कम मूल्य और असंगठित कार्य, सामाजिक मानदंड और दृष्टिकोण और विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने में कम भागीदारी।
व्यक्तियों और सामूहिक कार्यों दोनों द्वारा राजनीतिक संस्कृति को बदलना, उदाहरण के लिए राजनीतिक संरचना के बारे में शिक्षा देना, और राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है, जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच में सुधार करना और राय, आवाज और निर्णय लेने को प्रभावित करने के अधिकार के लिए नीति निर्माताओं द्वारा सम्मान बढ़ाना।
ऐसे क्षेत्रों में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए राजनीतिक व्यवस्था और प्रक्रिया में राजनीतिक भागीदारी और भागीदारी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपायों का उपयोग किया जा सकता है।

जागरूकता, शिक्षा और प्रशिक्षण

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue:3
December 2023
Impact Factor: 11.9
Subject: Political Sience

पर्याप्त राजनीतिक चेतना, ज्ञान, जागरूकता, शिक्षा और प्रशिक्षण के अभाव के कारण अधिकांश ग्रामीण महिलाएँ राजनीति में भाग लेने में असमर्थ हैं। उनमें से अधिकांश नहीं जानते कि राजनीति कैसे काम करती है, संस्थाएं लोगों को कैसे नियंत्रित करती हैं। उन्हें शिक्षित करके उनके कानूनी और राजनीतिक अधिकारों, चुनावी और राजनीतिक प्रणाली के बारे में जागरूक करना और गैर सरकारी संगठनों, महिला राजनीतिक शिक्षा मंच, स्वयं सहायता समूहों और महिला लोकतंत्र नेटवर्क की मदद से प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय और स्थानीय राजनीतिक दल को महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता और वकालत के लिए अभियान से संबंधित अल्पकालिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए।

महिलाओं की भागीदारी पर सामाजिक बाधाएँ

स्थापित सामाजिक और पारंपरिक संरचना द्वारा प्रस्तुत बाधाओं का समूह, जो जाति, लिंग, धर्म, कामुकता, विकलांगता और कई अन्य दीर्घकालिक सामाजिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक मानदंडों जैसे अशक्तिकरण और विशेषाधिकार के कुछ पैटर्न बनाता है, जो महिलाओं को इसमें भाग लेने से रोकता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और मतदाता दोनों के रूप में चुनावी प्रक्रिया। ये भेदभावपूर्ण कानून, प्रथाएं और संरचना महिलाओं को राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेने और नेता बनने से हतोत्साहित करते हैं। इन भेदभावों को दूर करना और कम करना राजनीतिक घटनाओं और अन्य सामाजिक गतिविधियों में अधिक भागीदारी और भागीदारी का रास्ता हो सकता है।

योग्यता विकास

कौशल और ज्ञान कम कुशल, कम उत्पादकता और लंबे समय तक काम करने वाले कम अवैतनिक नौकरियों में केंद्रित ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास और विकास के प्रेरक कारक हैं।

ग्रामीण महिलाओं को सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम, स्थापित औपचारिक और अनौपचारिक महिला कॉकस और राजनीतिक दलों के समर्थन के माध्यम से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और चुनावी प्रक्रिया और राजनीतिक घटनाओं से संबंधित राजनीतिक संस्थानों तक पहुंच बढ़ाने की क्षमता विकसित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

नीति विश्लेषण का समर्थन करना, मानव अधिकार शिक्षा को बढ़ावा देना, कौशल निर्माण जारी रखना और नेतृत्व, संचार, प्रबंधकीय और वित्त संबंधी कौशल विकसित करने के लिए ग्रामीण महिलाओं की क्षमता निर्माण के अन्य महत्वपूर्ण उपकरण हैं।

लिंग–समानता

हमारी धार्मिक प्रथाएँ हमारी पुरुष प्रधान राजनीतिक व्यवस्था और समाज को प्रतिबिंबित करती हैं। राजनीति को पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता है और सामाजिक–सांस्कृतिक मानदंडों और पारंपरिक संरचना के कारण महिलाओं को राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लेना चाहिए। हम

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue:3
December 2023
Impact Factor: 11.9
Subject: Political Sience

शिक्षा, रोजगार में लैंगिक भेदभाव, पुरुषों की तुलना में कम वेतन, सामान्य नागरिक अधिकार और यौन उत्पीड़न पाते हैं।

हम लड़कों और लड़कियों के बीच समान पालन–पोषण, सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने, मौजूदा कानूनों के कार्यान्वयन में वृद्धि, महिला उद्यमिता, परामर्श कार्यक्रम और राजनीतिक नेतृत्व के माध्यम से लैंगिक असमानता को कम कर सकते हैं। वर्तमान में जिले में महिला किसानों के लिए एक नीति की बुनियादी मांग होनी चाहिए, जिसमें कृषक, खेतिहर मजदूर, पशुपालक, पशुपालक और वन श्रमिक शामिल हैं। इसके बाद, भूमि पर उनके समान अधिकार और इनपुट क्रेडिट, बाजार और विस्तार सेवाओं तक पहुंच का बीमा किया जाना चाहिए।

सुरक्षा संबंधी मुद्दे

सुरक्षा के मुद्दों और बलात्कार, यौन उत्पीड़न के मामलों की चिंताजनक संख्या के बारे में सुनने वाली खबरों के कारण महिलाएं ज्यादातर समय बाहर काम करने में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। सामान्य तौर पर महिलाएं किसी भी समय उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट करने पर अपने बच्चों या अपनी सुरक्षा के लिए डरती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पुलिस परामर्श और कानूनी सेवाओं तक पहुंच अधिक कठिन हो सकती है। महिला सुरक्षा में रणनीतियाँ, प्रथाएं और नीतियां शामिल हैं जिनका उद्देश्य अपराध के डर सहित लिंग आधारित हिंसा को कम करना है। महिला सुरक्षा में सुरक्षित स्थान, गरीबी से मुक्ति, वित्तीय सुरक्षा और स्वायत्तता और आत्म–सम्मान शामिल है। कई समूहों ने महिला सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए कार्यशालाओं, सेमिनारों, शैक्षिक कार्यक्रमों, सम्मेलनों और मंचों जैसे मार्च, रैलियों और विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए।

निष्कर्ष

पिछले कुछ दशकों से और विशेषकर पिछले कुछ वर्षों में भारतीय महिलाओं ने नीतियों सहित गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में काफी प्रगति की है। फिर भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है।ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण आत्मविश्वास बढ़ाने, नेतृत्व गुणों को विकसित करने और उनके कानूनी और राजनीतिक अधिकारों के बारे में जागरूक होने के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करता है। महिला नेतृत्व उनके समुदायों विशेषकर अन्य महिलाओं और किशोरियों के लिए भी अनिवार्य है। जिले के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए महिला साक्षरता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, उनकी स्थिति की पहचान और राजनीतिक सशक्तिकरण से संबंधित प्रयास जारी रखने की जरूरत है। ग्रामीण महिलाओं में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) बढ़ाने में योगदान देने की अपार क्षमता है। यदि समानता की बाधाओं को दूर किया जाता है।

संदर्भ

[1]. लोरी बीमन और (2006) रोहिणी पांडेः महिला राजनेता, लिंग पूर्वाग्रह, और ग्रामीण भारत में नीति निर्माण

ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue:3
December 2023
Impact Factor: 11.9
Subject: Political Sience

[2]. बी. विसंदजी (2006) शैली अब्दुल अलीशा अप्लेः ग्रामीण भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारीः SAGE प्रकाशन wwwA u-k-sageup-com/home-nav
[3]. धारुबा हजारिका (2011): भारत में महिला सशक्तिकरणः एक संक्षिप्त चर्चा, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन खंड 1 नंबर 3 (2011) पृष्ठ–199–2002 में प्रकाशित
[4]. तिवारी, एस. (2012): ग्रामीण महिलाओं में राजनीतिक चेतना Boloji-com 28.01.2012।
[5]. धर्मेंद्र कुमार दुबे (2013): भारतीय हिमालय में ग्रामीण महिलाओं के बीच राजनीतिक चेतनाः कुमाऊं पहाड़ियों का एक अध्ययन। मानविकी और सामाजिक विज्ञान पर शोध खंड में प्रकाशित। 3 नंबर 1 (2013)
[6]. एस. मोल पी. भट्टाचार्य (2014): पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण। जर्नल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज रिसर्च वॉल्यूम में प्रकाशित। 3 क्रमांक 11–2014
[7]. पंचायत चुनाव रिपोर्ट (2014–15): राज्य चुनाव आयोग, बिहार

Author's Declaration

I as an author of the above research paper/article, hereby, declare that the content of this paper is prepared by me and if any person having copyright issue or patentor anything otherwise related to the content, I shall always be legally responsible for any issue. For the reason of invisibility of my research paper on the website/amendments/updates, I have resubmitted my paper for publication on the same date. If any data or information given by me is not correct, I shall always be legally responsible. With my whole responsibility legally and formally I have intimated the publisher (Publisher) that my paper has been checked by my guide(if any) or expert to make it sure that paper is technically right and there is no unaccepted plagiarism and hentriacontanes genuinely mine. If any issue arises related to Plagiarism/GuideName/EducationalQualification/Designation/Addressofmyuniversity/college/institution/Structure or Formatting/ Resubmission / Submission /Copyright /Patent/Submission for any higher degree or Job/Primary Data/Secondary Data Issues. I will be solely/entirely responsible for any legal issues. I have been informed that the most of the data from the website is invisible or shuffled or vanished from the data base due to some technical fault or hacking and

ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue:3
December 2023
Impact Factor: 11.9
Subject: Political Sience

therefore the process of resubmissions there for the scholars/students who finds trouble in getting their paper on the website. At the time of resubmission of my paper I take all the legal and formal responsibilities, If I hide or do not submit the copy of my original documents (Aadhar/Driving License/Any Identity Proof and Photo) in spite of demand from the publisher then my paper may be rejected or removed from the website anytime and may not be consider for verification. I accept the fact that as the content of this paper and the resubmission legal responsibilities and reasons are only mine then the Publisher (Airo International Journal/Airo National Research Journal) is never responsible. I also declare that if publisher finds any complication or error or anything hidden or implemented otherwise, my paper maybe removed from the website or the watermark of remark/actuality maybe mentioned on my paper. Even if anything is found illegal publisher may also take legal

नीरज कुमार ठाकुर,
डॉ. विनोद कुमार सैनी

****